(b) what is the number of the projects proposed to be set up in Kerala during 1989-90; and the money allocated therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DE VELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M ARUNACHALAM): (a) Of the applications for grant of Letters of Intent under Industries (Development and Regulation) Act. 1951 received from various Central / State Government Undertakings upto 31.12.1988, 43 applications are at various stages of processing.

(b) The Planning Commission have intimated that an outlay of Rs. 36.85 crores has been proposed for the year 1989-90 against an anticipated expenditure of Rs. 34.99 crores in the year 1988-89. Outlays for major groups of industries as proposed by the State Government for the year 1989-90 is enclosed in the enclosed Statement (See below)

Statement

Annual PLan 1989-90, Keraia-Large t Medium Industries

SI. No.	Scheme / Project	Outlay Proposed by State Govt.
		(Rs. lakhs)
1.	Cement & Non-Metallic Mineral Industries.	400.00
2.	Engineering Industries	380.00
3.	Electronics & Tele-communication Industries.	750.00
4.	Consumer Industries	135.00
5.	Promotional Institu-	2020.00
	TOTAL	3683.00

दिल्ली में औद्योगिक एककों के कार्यालय प्रतिष्ठानों पर व्यय

2019 **श्री राम जेठमलानी:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित अनेकों औद्योगिक संस्थानों के कार्यालय स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक संस्थानों की संख्या क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन संस्थानों के उत्पादन एकक दिल्ली से बाहर स्थापित हैं;

(घ) यदि हां, तो इनके कार्यालयों को दिल्ली में स्थापित करने का क्या औचित्य है; और

(ङ) इन कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर कितना वार्षिक खर्च होता है?

उद्योगमंत्री (श्री जे० वेंगल राव) :(क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशाय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र केउपक्रमों के कार्यालयों से है। ऐसे लगभग 180 कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इनमें से अधिकांश सम्पक/शाखा कार्यालय हैं। इन कम्पनियों में से अनेक के उत्पादन एकक दिल्ली से बाहर स्थित है।

(घ) सरकारी उद्यमों को दिल्ली में स्थित विभिन्न मंत्रालयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों / सम्बद्ध अभिकरणों के साथ परस्पर कार्य करना होता है। बहु-एकक संगठनों के मामलों में, जिनके विनिर्माणकारी एकक देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित हैं, उनके निगमित कार्यालय किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थित होने चाहिएं। कुछ कम्पनियां जैसे दिल्ली परिवहन निगम, महानगर टेलीफोन निगम लि०, भारत पर्यटन विकास निगम आदि मुख्यतः दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए स्थापित किये गये हैं

(ङ) दिल्ली में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या एक लाख से अधिक होगी। उनके वेतन तथा भत्तों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि कम्पनियों के लिये यह आंकड़े सरकार को भेजने अपेक्षित नहीं है। दिल्ली में तैनात कर्मचारियों की बड़ी संख्या तथा इसमें अंतर्ग्रस्त अनेक कम्पनियों को देखते हुए यह जानकारी एकत्र करने में जितने प्रयास करने होंगे, प्राप्त परिणाम उसके अनुरूप सिद्ध नहीं होंगे।